

भोपाल में 29 हजार वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायकों के आवास बनाने के लिए भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में 29 हजार पेड़ों को काटने के विरोध में जागरूक लोग चिपको आंदोलन कर रहे हैं। हरे-भरे और बड़े पेड़ों को कटने से रोकने के लिए महिलाएं और बच्चे भी इनसे चिपककर कह रहे हैं कि जान दे देंगे, पर पेड़ नहीं कटने देंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक इन लोगों ने अपने आंदोलन की कड़ी में सभी पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधे हैं।

पेड़ों को बचाने के इस आंदोलन की शुरुआत 12 जून को धरना से शुरू की गई थी। इसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान और कांग्रेसी भी शामिल हुए। इसके बाद आंदोलन के लिए जनसमर्थन जुटने लगा। स्थानीय लोगों ने गुरुवार से चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। दो दिन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के समर्थन में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग पेड़ों को बचाने के लिए आगे आ गए। पेड़ों से चिपके रहे और पेड़ों के कटने का विरोध कर रहे हैं। शासन से प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग तेज होने लगी है। हालांकि, इस बारे में अभी सरकार की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन शहर की दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, आंदोलनकारी सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं। वृक्ष मित्र सुनील दुबे, पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी, पर्यावरणविद् डा. सुभाष सी पांडे ने कहा कि सरकार जल्द नहीं मानती है तो एनजीटी, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहाँ, पार्षद

- मंत्री व विधायकों के आवास बनाने के लिए पेड़ काटने का ही रहा विरोध
- महिलाएं पेड़ों से चिपककर कह रही- जान चली जाए पर पेड़ नहीं कटने देंगे



भोपाल के शिवाजी नगर में 29 हजार पेड़ काटे जाने के विरोध में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से चिपककर विरोध करते आंदोलनकारी ● नईदुनिया

योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने कहा कि जब तक सरकार प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करती है, चिपको आंदोलन चला जारी रहेगा। एक भी पेड़ को नहीं कटने देंगे।

यह है प्रोजेक्ट : भोपाल के तुलसी नगर व शिवाजी नगर की 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। इसके तहत मंत्री व विधायकों के लिए आवास बनने हैं। यहां पर मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट व 230 विधायकों के लिए फ्लैट बनाए जाने हैं। अधिकारियों के बंगले भी बनने हैं। दोनों जगहों पर 29 हजार पेड़ों को काटा जाना है।